RAJYA SABHA

Wednesday, the 1st December, 1971/ the 10th Agrahayana, 1893 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR CHAIRMAN in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

JAMUNA SAND

358 SHRI RAM SAHAI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING/ **निर्माण और आवास मंत्री** be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn to the news item publised in the 'Nav Bharat Times' dated the 16th August, 1971, expressing concern over carrying out sand from the river Jamuna, and

(b) whether a lease for carrying out the Jamuna sand has been given, and if so, to whom and on what terms ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING/ **निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री** (SHRI I K. GUJRAL) : a) Yes, Sir.

(b) Sand is quarried from the rive Jamuna at three places viz Madanpur Khadar, Jasola and Okhla The lease ar Madanpur-khadar was given to the highest bidders, M/s Parmajit Sing Niamatullah for Rs 1,71,000 in 1965 for a period of five years The lease at Jasola was given to the highest bidder, Shri Dharambir Singh for Rs. 1,13,400/- in 1971 for a period of three years The lease for sand at Okhla was given by the Irrigation Department of the U. P. Government to M/s Abdul Majid Parmajit Singh in 1966 The terms and conditions of this lease are not known.

श्री राम सहाय : क्या मैं यह जान सकूगा कि यह जो रेत निकाला जा रहा है यह कितने मील लम्बे एरिया से निकाला जा रहा है और क्या इस बारे मे कोई ऐसा खयाल किया गया है कि इसके निकालने से हानि होगी या लाभ होगा !

SHRI I. K GUJRAL : What is the question ?

MR. CHAIRMAN : "What is the area covered by these activities and what is the probable loss or gain?" That is the question.

SHRI I. K. GUJRAL : Sir sor-far as the gain is concerned, we have auctioned sites and we have given the price at which they were sold One of the places at Madanpur-Khadar did not remain operative because access to the quarry was not available. Now, the land has been acquired and access may now be available. The entire approach now seems to be that the entire Jamuna bed has been divided into three parts (1) above Jamuna Bridge; (2) below Jamuna Bridge and (3) below Okhla. These seem to be the three broad dimensions in which the problem is being dealt with. So far as Government's benefit is concerned, Government benefit in two ways, firstly, we sell the quarry and secondly, the Government charges also the royalty for the actual exacavation of sand

श्री राम सहाय : क्या मैं माननीय मत्री महोदय से जान सकूगा कि वहा आसपास के जो मकान है शाहदरा मे उन पर इसका कोई विपरीत प्रभाव तो नही पडेगा !

श्री आई० के० गुजराल : जमुना का सैड निकालने से मकानों पर अच्छा असर पडना चाहिए । उससे बेड डीपर हो जाता है, पानी ऊपर नही आता और इससे उनको फायदा होना चाहिए ।

SCHOOL SCIENCE PILOT PROJECT

359. SHRI SITA RAM KESRI : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE /**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** be pleased to state :

(a) whether the National Council of Educational Research and Training has initiated a School Science Pilot Project,

(b) if so, the broad outlines of the Scheme; and

(c) the number of States that have joined the scheme ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE / **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय मे उप-मंत्री** (PROF D. P. YADAV) : (a) The Government of India is implementing a Project for the improvement of Science teaching at the School stage with the assistance of UNESCO and UNICEF. The NCERT has been entrusted with cerain responsibilities under this Project;

(b) The Scheme provides for :

(i) development by the NCERT of new syllabi text-books and related instructional materials with the assistance of UNESCO. States and Union Territories will be assisted to translate the books into the major local languages and print trial editions of the same.

(ii) training of science educators and science teachers at different levels by the NCERT and State Governments.

(iii) Supply by UNICEF of laboratory equipment to selected teacher training institutions and new science kits to selected schools.

(iv) supply of one mobile laboratory for each district and one vehicle for the Science supervisory personnel at the State level.

To start with, the new text-books and instructional materials are being tried in 50 primary and 30 middle schools in each State and Union Territory that have agreeed to implement the scheme. Books will be supplied free to all children in the schools selected for the pilot project. As a result of the experience gained from this experiment, the States are expected to prepare revised versions for text-books adapted to local conditions and to introduce them in all their schools according to a phased programm .

(c) All S [illegible] and Union Territories have agi[illegible] [illegible] [illegible]e scheme. 17 States and 4 [illegible] [illegible]ories have so far started im[illegible] [illegible]ing he scheme. These are :—

1. Andhra P
2. Assam
3. Bihar
4. Gujarat
5. Haryana
6. Himachal Pradesh
7. Jammu & Kashmir
8. Kerala
9. Madhya Pradesh
10. Maharashtra
11. Mysore
12. Nagaland
13 Orissa
14. Punjab
15 Rajasthan
16. Tamil Nadu
17. Uttar Pradesh
18. Delhi
19. Goa
20. Pondicherry
21. Tripura

MR CHAIRMAN : Mr. Minister, this is a very long answer, Would it not have been convenient to put it in the shape of a written statement and lay it on the Table of the House ?

SHRI ARJUN ARORA : He is new, Sir. He is gaining experience

श्री सीताराम केसरी : सभापति जी, आप के द्वारा शिक्षा मत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए अभी जो आप ने कहा कि यूनेस्को और यूनीसेफ के द्वारा आपको कुछ सामग्री मिली है तो मै जानना चाहूंगा कि आप को यूनोस्को से और सट्रल गवर्नमेंट से कितना पैसा इसके ऊपर खर्च करने के लिए मिला है? दूसरे (ख) आप ने स्टेट वाइज कितनी इस तरह की शिक्षण संस्थाओं की योजना बनायी है ? हर स्टेट मे कितने-कितने प्राइमरी और मिडिल स्कूलो को इस योजना में लेने का फैसला किया है ? और (ग) बिहार के कितने प्राइमरी और कितने मिडिल स्कूलों को इस योजना मे लेने का आप का विचार है ?

प्रो० डी० पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, यूनेस्को और यूनीसेफ से कुल मिला

कर प्रथम चरण में हम लोगों को 21,82,200 डालर की सहायता मिली है जो कपलीशन की स्टेज में है और 556 की इंस्टीट्यूशन्स हैं जहां टीचर्स ट्रेनिंग होती है, उनको इक्विपमेंट हम भेज चुके हैं। पुनः अब हमको करीब-करीब 70,22,000 डालर की सहायता मिली है जिसमें हम 60,000 स्कूलों में साइंस किट्स भेज सकेंगे। बिहार का जहां तक सवाल है, बिहार सरकार जितना चाहेगी उतना उनको मिलेगा, लेकिन पहले वह अपनी उसे खर्च करने की क्षमता बनावे।

श्री सीताराम केसरी : आपके डाइरेक्टर महोदय ने दिनांक 22 सितम्बर को अपने स्टेटमेंट में बताया है कि यह योजना इतनी अच्छी है कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने इनके लिए डिमाड की है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन की डिमांड, उन की इस इस मांग पर आप ने कोई कार्य प्रारम्भ किया है और उसकी सप्लाई करने से क्या आपको फारेन एक्सचेज मिलेगा और क्या रायल्टी आप उस पर लेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं।

प्रो० डी० पी० यादव : यह विचाराधीन है और हमारी सरकार और एन० सी० ई० आर० टी० यह जरूर चाहते हैं कि साउथ एशिया में एन० सी० ई० आर० टी० के द्वारा जो किताबें बनायी जायं उनके प्रकार हो। जहां तक रायल्टी का सवाल है हम नामिनल रायल्टी पर उसे देने को तैयार हैं।

श्री निरंजन वर्मा : क्या यह संपूर्ण योजना जो चालू की जा रही है उस पर नियंत्रण केन्द्र का रहेगा या केन्द्र का और स्टेट का दोनों का नियंत्रण उस पर रहेगा और इसी प्रकार से जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं उन राज्यों को भी इसमें वित्तीय सहायता देने के लिए आप आमन्त्रित करेंगे या स्वयं उन्होंने इस प्रकार का सजेशन दिया है कि वह आपके साथ मिल कर वित्तीय सहायता का भार वहन करेंगे ?

प्रो० डी० पी० यादव : तत्काल हम 70,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में जो किट्स देंगे उनका खर्च एन० सी० ई० आर० टी० के माध्यम से यूनीसेफ दे रहा है। जो मेंटेनेंस कास्ट होगी वह राज्य सरकार को देनी होगी। प्रश्नोत्तर में मैंने कहा है कि हम प्रत्येक राज्य को एक मोबाइल वैन भी दे रहे हैं लेबोरेटरी, गश्ती प्रयोगशाला और एक गाड़ी सुपरवाइजरी पर्सोनिल के लिए दे रहे हैं। यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह कितना हम से ले सकती है।

श्री निरंजन वर्मा : नियंत्रण किस का होगा ?

प्रो० डी० पी० यादव : हम तो इक्विपमेंट दे देंगे। यह तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि उन का स्कूलों में कैसे, किस प्रकार से यूज किया जा रहा है।

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ साइंस की पुस्तकें जो स्कूलों के बच्चों के लिये एन० सी० ई० आर० टी० के द्वारा तैयार की गई हैं वह इतनी क्लिस्ट और इतनी टक्नीकल हैं कि उनके बारे में आम तौर पर स्कूलों के अध्यापकों, प्रिंसिपलों और बच्चों के अभिभावकों को यह शिकायत है कि बच्चों को वह समझ में आना तो दूर रहा उनके पिता भी समझने की कोशिश करें तो उनकी भी समझ में नहीं आता ! इतनी क्लिष्ट और टेकनिकल साइंटिफिक टर्मिनालाजी जो है उसकी न तो बच्चो को जरूरत है और न वह उनके लिये कोई उपयोगी होगी। तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायतें आई है और अगर आई हैं तो क्या आप इसकी कोई जांच करायगें कि बच्चों के ऊपर अनावश्यक बोझ डालने का क्या उपयोग है !

प्रो० डी० पी० यादव : इसके लिये इवेलुयेशन की स्कीम है और एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हो सकता है कि कुछ खामियां हों लेकिन हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 142 सेंट्रल स्कूलों में उसमें हमने पाया है कि एन० सी० ई० आर० टी० की जितनी भी किताबें विज्ञान की हैं वह बहुत ही उपयोगी हैं। यह निर्भर करता है इस पर कि शिक्षक उसे किस इंटरेस्ट से पढ़ा रहे हो।

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय जरा कभी उन पुस्तकों को देखें और अगर स्वयं मंत्री महोदय उनका अर्थ समझ सकेंगे तो मैं मान लूंगा कि वे बड़ी उपयोगी हैं।

प्रो० सैयद नरुल हसन : यह साइंस के उस्ताद रह चुके हैं, ऐसी बात न कह दीजिए।

डा० भाई महावीर : मेरा निवेदन है, महोदय, कि स्कूलों के प्रिंसपल, दिल्ली के स्कूलों के जो प्रिंसीपल हैं उनको भी यह शिकायत है।

MR. CHAIRMAN : Next question.

*101. [*The questioner (Sardar Gurcharan Singh Tohra) was absent. For answer* vide *col.* 33 infra.]

AFFILIATION OF COLLEGES TO THE PUNJAB UNIVERCITY, CHANDIGARH AND GURU NANAK UNIVERSITY, AMRITSAR

*360. SHRI K. C. PANDA :
SHRI M. K. MOHTA:†
SHRI LOKANATH MISRA :
SHRI SUNDAR MANI PATEL :

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE / **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** be pleased to state :

(a) whether there are serious differences between the Punjab University, Chandigarh, and the Guru Nanak University, Amritsar, over affiliation of certain colleges to the two universities;

(b) whether this has jeopardised the studies of thousands of students of these Universities; and

(c) if the answer to part (a) and (b) be in the affirmative whether Government have received any report from these Universities, and if so, the reaction of Government in this regard ?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri M. K. Mohta.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE / **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री** : (PROF. S. NURUAL HSAN) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

SHRI M. K. MOHTA : Sir, the answer of the hon. Minister is really intriguing, because there was definitely a dispute about the affiliation of several colleges between the Guru Nanak. University and the Punjab University. Perhaps the dispute has been resolved of which we are not aware, and therefore, the hon. Minister has said that there is no dispute now. I would request the hon. Minister to clarify in what way the dispute has been settled between the two universities and what the present position is. That is my first question.

MR. CHAIRMAN : A resolved dispute is no dispute.

SHRI M. K. MOHTA : But at the time notice was given, there was a dispute, Sir. The position may be different to-day.

SHRI ARJUN ARORA : According to him, the dispute should have persisted at least till to-day so that he could put a convenient supplementary.

PROF. S. NURUL HASAN : Sir, I have contacted the Vice-Chanceller of Guru Nanak University, the Registar of Punjab University, Chandigarh the Vice-Chancellar was not available and Dr. Dutt of the D. A. V. College Managing Committee. and all the three of them have said that there is no dispute. I do'nt think it would be proper for us now to go into the history of the dispute since all the three parties are satisfied.